



# अखंड भारत संदेश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज

सोमवार 2 फरवरी 2025

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को दुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेंट

# टैरिफ का काउंटर,

# इंडस्ट्री को बूस्ट लेकिन मिडिल क्लास निराश...

## बजट में बड़ा बदलाव

### विदेशी संपत्ति और टैक्स छिपाने पर नहीं होगी जेल



केंद्र सरकार की ओर से यूनिन बजट 2026 में टैक्स को लेकर किसी बड़े बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि सरकार ने नियमों में ऐसे बदलाव किए हैं, जिनसे कुछ लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर विदेश में रहने वाले एनआरआई और ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अब तक विदेश में मौजूद अपनी छोटी-मोटी संपत्तियों की जानकारी साझा नहीं की थी।

रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। सरकार टैक्स सिस्टम को ज्यादा व्यावहारिक बनाना चाहती है। इस बार बजट की चर्चा एनआरआई और विदेशी संपत्तियों के खुलासे से जुड़े नियमों पर भी हो रही है। आइए जानते हैं, इनको लेकर क्या बदलाव किए गए हैं?

विदेशी छोटी संपत्तियों के खुलासे पर सरकार की नरमी बजट में उन लोगों को राहत देने का फैसला लिया गया है, जो विदेश में मौजूद अपनी छोटी-मोटी संपत्ति की जानकारी टैक्स रिटर्न में भूलवश नहीं दे पाए थे। अगर किसी व्यक्ति

की गैर-अचल विदेशी संपत्ति की कुल कीमत 20 लाख रुपये से कम है और वह उसका खुलासा नहीं करता है, तो उस पर अब कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में सजा से छूट मिलेगी। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा, जिससे सीमित विदेशी एसेट्स रखने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इनकम टैक्स मामलों में जेल की सजा खत्म

सरकार की ओर से बजट 2026 में टैक्सपेयर्स की बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का फैसला लिया गया है। अब अगर किसी व्यक्ति की आय में गड़बड़ी पाई जाती है या फिर टैक्स छिपाने का मामला सामने आता है, तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में केवल जुर्माना का प्रावधान किया गया है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत लागू किया जाएगा, जिससे ईमानदार करदाताओं को कानूनी परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।



## विकसित भारत की उड़ान के लिए मजबूत नींव



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 को भारत के विकसित भारत 2047 के सफर की मजबूत नींव बताते हुए इसकी सराहना की और कहा कि यह देश में चल रही 'सुधार की रफ्तार' को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने लगातार नौवां बजट पेश किया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत 2047 के सपने की उड़ान के लिए एक मजबूत नींव है। यह बजट भारत में चल रही 'सुधार की रफ्तार' को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। अभूतपूर्व सुधारों ने भारत के साहसी और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए खुले आसमान के नीचे विकास के अवसर प्रदान किए हैं। हमारा प्रयास कौशल, व्यापकता और स्थिरता को निरंतर मजबूत करना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक सबसे बड़ी संपत्ति हैं और सरकार ने उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके नागरिक होते हैं। हाल के वर्षों में, हमारी सरकार ने अपने नागरिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। राजकोषीय और आर्थिक रणनीति पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक ऐसा अनूठा बजट है जो राजकोषीय घाटे को कम करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रण

में लाने पर केंद्रित है और इसके साथ ही, इस बजट में उच्च पूंजीगत व्यय और उच्च विकास का संयोजन भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को और मजबूत करता है। भारत के 14 करोड़ नागरिक न केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट हैं, बल्कि हम जल्द से जल्द तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। यह देश के करोड़ों नागरिकों का संकल्प है। विश्व के एक विश्वसनीय, लोकतांत्रिक सहयोगी और एक विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण आपूर्तिकर्ता के रूप में, भारत की भूमिका निरंतर विस्तारित हो रही है। भारत द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित व्यापार समझौतों - सर्वव्यापी समझौतों की जननी - का अधिकतम लाभ भारत के युवाओं और भारत के लघु एवं मध्यम उद्योगों को मिलना चाहिए। इस दिशा में बजट में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने आगे कहा, "इस बजट में नारियल, कोको, काजू और चंदन की खेती करने वाले किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय भी शामिल हैं।" प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में, महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में, महत्वपूर्ण उपाय किए।

# भारतीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का प्लान सुधारों का सिलसिला जारी रहेगा- निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट के बाद अपनी पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार विकास की गति को बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने वित्त मंत्रालय के सभी सचिवों के साथ कहा कि मुख्य रूप से, हम संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो जारी रहेगा। सुधार किए जा चुके हैं। हम सुधार गतिविधियों को जारी रख रहे हैं। इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वातावरण बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि 21वीं सदी पूरी तरह से प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है। इसलिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रौद्योगिकी का लाभ आम आदमी को मिले। निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहर भारत के विकास, नवाचार और अवसरों के इंजन हैं। सरकार अब द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों, और यहां तक



??कि मंदिर-नगरों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जिन्हें आधुनिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। इस बजट का उद्देश्य विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर शहरी आर्थिक क्षेत्रों (सीईआर) का मानचित्रण करके शहरों की आर्थिक शक्ति को और अधिक बढ़ाना है। सुधार-सह-परिणाम आधारित वित्तपोषण तंत्र के साथ चुनौती मोड के माध्यम से

उनकी योजनाओं को लागू करने के लिए 5 वर्षों में प्रति सीईआर 5000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रति शहर प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं, और मुख्य जोर द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों पर होगा। वित्त मंत्री ने बजट के दो महत्वपूर्ण पहलुओं, सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण

योजना पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन में दो प्रमुख घोषणाएं की गई हैं जिनसे भारत की ऊर्जा क्षमता और बौद्धिक संपदा संबंधी मामलों में सुधार होगा। 40,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण योजना इलेक्ट्रॉनिक्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। हमने दुर्लभ पृथ्वी गलियारों की स्थापना की भी घोषणा की है

ताकि भारत अपनी सामग्रियों की आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सके। इसलिए, एक बार जब हम इन खनिजों की पहचान कर लेंगे, उनका अन्वेषण और प्रसंस्करण कर लेंगे और उन्हें हमारे लिए उपलब्ध करा लेंगे, तो दुर्लभ खनिजों को आयात करने के लिए बाहरी स्रोतों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने उन राज्यों की पहचान कर ली है जहां हम ये दुर्लभ खनिज गलियारे स्थापित करना चाहते हैं। ये गलियारे ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं और इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुआयामी प्रभाव पड़ेगा। चुंबक और दुर्लभ खनिजों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। 2026-27 के बजट में, गैर-ऋण प्राप्ति और कुल व्यय क्रमशः 36.5 लाख करोड़ रुपये और 53.5 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं। केंद्र की शुद्ध कर प्राप्ति 28.7 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं।

## धड़ाधड़ बनेंगी मिसाइलें और फाइटर जेट, निर्मला सीतारमण ने खोला 7.8 लाख करोड़ का खजाना

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा मंत्रालय को 77.8 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है। इसमें से 72.19 लाख करोड़ केवल सेनाओं के आधुनिकीकरण (कैपिटल आउटले) के लिए रखे गए हैं। रक्षा मंत्रालय के कुल बजट में इस साल करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कैपिटल आउटले में 21.84 प्रतिशत का इजाफा किया गया है - जो पिछले साल के 21.80 लाख करोड़ से बढ़कर 72.19 लाख करोड़ पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के सामने आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनमें नए लड़ाकू विमान (जैसे राफेल), पनडुब्बियां और ड्रोन् की खरीद शामिल है। इन सौदों का मकसद

थलसेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत को और मजबूत करना है। डिफेंस बजट (सिविल) में पिछले साल के 228,554.61 करोड़ की तुलना में 0.45 प्रतिशत की मामूली कमी की गई है। डिफेंस सर्विसेज (रेवेन्यू) को 23,65,478.98 करोड़ कैपिटल आउटले को 22,19,306.47 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो क्रमशः 17.24% और 21.84% की बढ़ोतरी दिखाते हैं। पेंशन बजट भी बढ़ा सरकार ने रक्षा पेंशन के लिए भी राशि बढ़ाते हुए 1,71,338.22 करोड़ आवंटित किए हैं, जिससे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।













## सड़क हादसे में एक की मौत, तीन घायल



### अखंड भारत संदेश

**पट्टी।** थाना आसपुर देवसरा क्षेत्र के अंतर्गत अमरगढ़-पट्टी मार्ग पर सेतापुर गांव के सामने सोमवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गई। अमरगढ़ की ओर जा रहे एक बाइक सवार की सामने से आ रही मारुति वैन से आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कुल चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सेतापुर गांव निवासी सुरेश पुत्र ननकू और अनिल रजक (38) बाइक से अमरगढ़ बाजार जा रहे थे। इसी

दौरान अमरगढ़ की ओर से आ रही मारुति वैन से उनकी टक्कर हो गई हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मारुति वैन चालक लालचंद जायसवाल निवासी ढकवा थाना आसपुर देवसरा तथा वैन में सवार आफताब आलम निवासी ग्राम छतौना थाना आसपुर देवसरा भी चोटिल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक और वैन दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।सूचना मिलते ही आसपुर देवसरा पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी अमरगढ़ भेजा। प्राथमिक

## भाजपा नेता के आवास पर आयोजित

### हुआ बजट भाषण का लाइव प्रसारण



### अखंड भारत संदेश

**प्रतापगढ़।** नगर पंचायत गड़वारा के डंडरी वार्ड निवासी भाजपा नेता नवीन सिंह के आवास पर बजट भाषण का लाइव प्रसारण देखने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला मंत्री अनुराग मिश्र ने लोगों को बजट की खूबियाँ बताईं। कहा कि यह बजट गरीब किसानों, मजदूरों के लिए लाभप्रद साबित होगा। भाजपा अंतू मंडल अध्यक्ष राजाराम वैश्य के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बजट भाषण के साथ एसआईआर

अभियान पर कार्यकर्ताओं से विशेष फोकस करने का आग्रह करते हुए फार्म 6 के माध्यम से अधिक से अधिक मतदाताओं के नाम जुड़वाने के अभियान पर बजट भाषण का आह्वान किया।भाजपा नेता नवीन सिंह ने राजाराम वैश्य, अनुराग मिश्र समेत आए हुए सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का स्वागत समाना किया।हस मौके पर मंडल महामंत्री महेश गुप्ता, शक्ति केंद्र प्रभारी राजेश पाण्डेय, मंडल मंत्री अंजनी पाण्डेय, सत्यप्रकाश मिश्र, रामचरित मिश्र, नितिन शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष शिव विलास वैश्य, सुधीर मोदी आदि मौजूद रहे।

## प्रमोद व मोना ने बजट को बताया किसान

### बेरोजगारों, युवा व उद्योग विरोधी

**लालगंज।** राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता सांसद प्रमोद तिवारी एवं क्षेत्रीय विधायक व नेता कांग्रेस विधानमण्डल दल आराधना मिश्रा मोना ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह ऐसा बजट है जो एक झुनझुने की तरह दिखता तो है परन्तु भ्रष्टाचार से भरा है। यह बजट किसान विरोधी, बेरोजगार व नौजवान विरोधी, लघु एवं मध्यम वर्ग विरोधी बजट है। यह बजट देश को निराशा देने वाला है। इसीलिए संसेक्स में 2300 शेयर की गिरावट आयी है। सांसद प्रमोद तिवारी व विधायक मोना ने कहा कि पिछले एक साल से पूंजी निवेश रूका हुआ है। अब न तो विदेशी निवेश हो रहा है और न ही स्वदेशी निवेश हो रहा है। नेता द्वय ने कहा कि बजट के बाद इसमें और भी गिरावट आयेगी। मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट भयंकर

घाटे वाला बजट है। सांसद प्रमोद तिवारी व विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि चालू वर्ष में राज्य प्राप्तियाँ ₹0 78086 करोड़ और नेट टैक्स संग्रह ₹0 162748 करोड़ कम रहा, जो आर्थिक सुस्ती का साफ संकेत है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग सहित महत्वपूर्ण योजनाओं के बजट में बड़ी कटौती की गयी है। जैसे स्वास्थ्य में 3686 करोड़ की कटौती, शिक्षा में 6701 करोड़, समाजकल्याण में 9999 करोड़, कृषि में 6985 करोड़, ग्रामीण विकास में 53067 करोड़, नगर विकास में 39573 करोड़, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति निमला सौतारमण जब बजट प्रस्तुत कर रही थीं तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के चेहरों पर निराशा और हताशा साफ झलक रही थी। वित्तमंत्री निर्मला सौतारमण के कुल नौ बजट में यह सबसे खराब बजट है, इस बजट से आज देश को निराशा हुई है।

## कंबल वितरण कर जनसेवा के माध्यम से दी



**प्रतापगढ़।** सचैली गांव में भाजपा नेता संत तिवारी की माता स्वर्गीय आशा तिवारी की प्रथम पुण्य स्मृति के अवसर पर कंबल वितरण एवं सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनसेवा को सर्वोच्च मानते हुए सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर पुण्यात्मा की सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी दिव्या मिश्रा ने कहा कि ह्रसेवा और संवेदना ही किसी पुण्यात्मा की स्मृति

को जीवंत रखने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है।ह्द उन्होंने इस प्रकार के सामाजिक आयोजनों को समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे पूर्व मंत्री इंदु प्रकाश राम प्रसाद एसडीएम फैजाबाद भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव पूर्व जिला अध्यक्ष हरि ओम मिश्रा पूर्व मंत्री शिवाकांत आश्रम मनोज तिवारी, विजय द्विवेदी संतोष मिश्रा आशुतोष त्रिपाठी अवनीश पांडे बृजेश मिश्रा पंकज वर्मा अवधेश मिश्रा दिवेश तिवारी महेश

उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए सभी को जिला अस्पताल प्रतापगढ़ रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान सेतापुर गांव निवासी अनिल कुमार कनौजिया की मौत हो गई।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। इस संबंध में आसपुर देवसरा थाना अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने बताया कि एक की मौत हुई है। तीन गंभीर रूप से घायल है जिनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है, और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

## युवा राष्ट्र के कर्णधार और भाग्य विधाता है : प्रमोद

**प्रतापगढ़।** राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रतापगढ़ नगर द्वारा युवा वन बिहार कार्यक्रम चलबिला के साईं दाता कुटी स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में संपन्न हुआ। वन बिहार कार्यक्रम परम पवित्र भगवाध्वज के सानिध्य में युवा स्वयंसेवकों ने विविध प्रकार के ऊर्जा और उत्साह भरने वाले शारीरिक एवं बौद्धिक कार्यक्रम हुए जिसमें युवाओं की कबड्डी प्रतियोगिता,बौद्धिक प्रतियोगिता जैसे पहेलियों का जवाब,अत्याक्षरी आदि रोचक ढंग से हुआ। वन बिहार कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता बोलते हुए काशी प्रांत के सह प्रांत महाविद्यालयीन विद्यार्थी कार्य प्रमोद ने कहा कि वन बिहार कार्यक्रम प्रकृति के सानिध्य में आयोजित एक वार्षिक मिशन समारोह है, जिसका मुख्य स्वयंसेवकों में अनुशासन,शारीरिक क्षमता,टीम भावना,सामाजिक समरसता और राष्ट्र के प्रति समर्पण को बढ़ावा देना है,इसमें खेल, बौद्धिक सत्र और सहभोज (एक साथ भोजन) प्रमुख गतिविधि होते हैं,जो स्वयंसेवकों को ऊर्जावान बनाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

## इंडियन प्रेस काउंसिल कुंडा तहसील इकाई का चुनाव सम्पन्न

### संदीप साहू अध्यक्ष व राहुल यादव महामंत्री निर्वाचित

### अखंड भारत संदेश

**कुंडा।** इंडियन प्रेस काउंसिल की तहसील इकाई कुंडा का चुनाव रविवार को तहसील स्थित पंचवटी परिसर में शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रीय संयोजक वीसी मिश्रा की देखरेख में संपन्न कराई गई। चुनाव अधिकारी राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनंद शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप कुमार विश्वकर्मा एवं संरक्षक अजय मिश्रा ने पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष व सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया।

चुनाव में तहसील क्षेत्र के पत्रकारों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। अध्यक्ष पद के लिए संदीप साहू,संदीप यादव एवं अजय मिश्रा ने नामांकन किया था, जबकि महामंत्री पद पर राहुल यादव और हसीबुल्लाह आमने-सामने थे। कुल 34 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का



प्रयोग किया।मतगणना के उपरांत अध्यक्ष पद पर संदीप साहू को 17 मत प्राप्त हुए, जबकि अजय मिश्रा को 11 और संदीप यादव को 6 मत मिले। इस प्रकार संदीप साहू को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं महामंत्री पद के लिए राहुल यादव को 27 मत तथा हसीबुल्लाह को 7 मत प्राप्त हुए, जिसमें राहुल यादव महामंत्री चुने गए।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष पद पर प्रमोद आजाद, अखिलेश त्रिपाठी एवं अजय मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोनू मिश्रा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष राम भुआल, कोषाध्यक्ष अमित पटेल, मीडिया प्रभारी अर्जुन धनगर,

संगठन मंत्री अमित अग्रहरि तथा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शिव मोहन यादव, सौरभ कुशवाहा एवं सुभाष सोनकर को निर्विरोध निर्वाचित किया गया।चुनाव परिणाम घोषित होते ही नव निर्वाचित पदाधिकारियों का फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रांतीय संगठन मंत्री शिवाकांत पांडेय, काशीराम राणा, अध्यक्ष लोकेश मिश्रा, दुर्गेश त्रिपाठी, दिनेश पाल, दिलीप साहू, देवेन्द्र अग्रहरि, शिवेंद्र तिवारी, कृष्ण प्रताप, विकास पांडेय, सतीश, छोटेलाल सहित बड़ी संख्या में पत्रकार साथी मौजूद रहे।

### महिलाओं को सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

**प्रतापगढ़।** मिशन शक्ति अभियान के तहत सांगीपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी दी। इसके साथ ही पुलिस टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को वूमन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090, महिला हेल्पलाइन 181 समेत 1076, 112, 1098, 1930 आदि हेल्पलाइन नंबरों के बाबत जानकारी देते हुए जागरूक किया। पुलिस टीम ने उन्हें किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना पर पुलिस से बेझिझक सम्पर्क करने पर त्वरित कार्रवाई होने के प्रति विश्वास दिलाया।

### भौतिकी विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा दो फरवरी को

**लालगंज।** नगर स्थित राम अंजोर मिश्र इण्टर कालेज में यूपी बोर्ड की कक्षा बारह की भौतिक विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा आगामी दो फरवरी सोमवार को सुबह नौ बजे से आयोजित होगी। भौतिक विज्ञान प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने उक्त जानकारी देते हुए सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से समय से विद्यालय पहुंचने को कहा है।

## जयन्ती समारोह का सृजना

### कुटीर मे हुआ आयोजन



**प्रतापगढ़।** सृजना साहित्यिक संस्था उत्तर प्रदेश के तत्वावधान मे सन्त शिरोमणि रविदास जयन्ती का आयोजन सृजना कुटीर अजीतनगर मे किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉ॰ दशराम मोर्य रत्न ने कहा कि आडंबर विरोधी एवं छुआछूत विरोधी महासंत रविदास का जीवन समता बन्धुता व न्याय का द्योतक है। मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी रोशनलाल ऊमरवैश्य ने कहा कि संत रविदास

का जीवन पंथनिरपेक्षता मानवता व सामाजिक न्याय का परिचायक है। विशिष्ट अतिथि के रूप मे चेयरपर्सन डॉ॰ शाहिदा ने कहा कि संत रविदास की जीवनयात्रा प्रत्येक युग के लिए अनुकरणीय है। इस अवसर पर साहित्यकार प्रेम कुमार प्रेम कुंज बिहारी काकाश्री श्रीनाथ सरस अमरनरथ जेजोड राधेश्याम दीवाना राजेश हर्षपुरी आदि ने अपने दिवाचन अर्पित कुमार निलय ने किया।

## स्कूल में आयोजित खेलकूद

### प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाया दमखम



**लालगंज।** धधुवागाजन लालगंज स्थित आईस्टीन पब्लिक स्कूल में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने दमखम दिखाया। विद्यालय की निर्देशिका श्रुति शुक्ला ने खेलकूद का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं आज हर क्षेत्र में लोहा मनवा रही है। संरक्ष विभव भूषण शुक्ल व डा. सौरभ मिश्र ने भी खेलकूद प्रतियोगिता पर अपने विचार

रखे। वहीं छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मंत्रमुग्ध किया। प्रतियोगिता में रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस एवं एलो हाउस के बीच लीवावाल, कबड्डी, ऊँची कूद, लम्बी कूद आदि का आयोजन हुआ। जिसमें ब्लू हाउस की टीम चैम्पियन रही। प्रधानाचार्य सुभांशु सिंह ने बच्चों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर योगेन्द्र शुक्ल, आर्नैडसिल्ला, महेंद्र पाठक आदि मौजूद रहे।

## अखंड भारत संदेश

## न्यूज झरोखा

### धर्मेन्द्र बने बाबा देवघाट महादेवन धाम के कार्यकारी अध्यक्ष

**प्रतापगढ़।** मोहनगंज बाजार के समीप स्थित बाबा देवघाट महादेवन धाम को मजबूती प्रदान कराने की मंशा को लेकर संस्थके विस्तार के क्रम में जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ता धर्मेन्द्र सिंह को बाबा



देवघाट महादेवन धाम का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। संस्थान के फाउंडर अध्यक्ष शील कुमार सिंह गहलौत ने बताया कि किसी भी संस्थान की मजबूती उसके कार्यकर्ताओं से प्रदान होती है। इसके लिए लगनशील जिम्मेदार एवं ईमानदार नेतृत्वकर्ता का होना जरूरी होता है। धर्मेन्द्र सिंह एक युवा जुझारू व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति है ऐसे में संस्थान के लिए एवम वर्य प्रदान होगी। बताया कि कार्यकारी संस्थान में 11 संरक्षक, 05 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 05 उपाध्यक्ष, 05 कनिष्क उपाध्यक्ष, 05 महासचिव, 05 सचिव, 05 उप सचिव, 01 कोषाध्यक्ष, 11 विधिक सलाहकार और 51सदस्य मनोनीत किया जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद धर्मेन्द्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि बाबा देवघाट महादेवन धाम के समुचित विकास एवं संस्थान के मजबूती के लिए हर संभव सार्थक प्रयास करूंगा और संस्थान के पदाधिकारियों एवं भक्तों की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इस दौरान संस्थान के महंत पुजारी रामानन्द गिरी महाराज पदाधिकारी विजय कुमार गुप्ता पुजारी शिव आसरे गिरी महाराज मौजूद रहे।

### आज होगी प्राण प्रतिष्ठा, पदयात्रा में उमड़ा जनसैलाब

**पट्टी।** तहसील के सरसतपुर गांव में भगवान शिव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न होगा। इसके पूर्व ग्रामवासियों द्वारा शिव मूर्ति को लेकर बाबा बेलखरनाथ धाम तक भव्य पदयात्रा निकाली गई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनोद मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पदयात्रा में समस्त ग्रामवासी श्रद्धा भाव से शामिल हुए। बाबा बेलखरनाथ धाम में दर्शन-पूजन के उपरांत शिव मूर्ति को गांव लाया गया, जहां विधि-विधान से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।इस धार्मिक आयोजन के दौरान ग्राम प्रधान पुष्पा देवी मिश्रा, राकेश तिवारी, प्रमोद मिश्रा, फूलचंद तिवारी, नंदलाल तिवारी, विपिन तिवारी, धर्मेन्द्र तिवारी, प्रदीप मिश्रा, नरेंद्र सिंह पटेल, संतोष गौतम, अमर सिंह पटेल, नरेंद्रलाल गुप्ता सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे।

### वृद्ध के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी

**पट्टी।** कोतवाली क्षेत्र के भोलापुर गांव निवासी दुर्गा प्रसाद अपने घर पर ही किराना की दुकान चलाते हैं। पीड़ित वृद्ध का आरोप है कि गांव का ही एक युवक आए दिन उन्हें परेशान करता रहता है।रविवार की देर शाम आरोपी युवक शराब के नशे में धुत होकर दुकान पर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने वृद्ध दुकानदार के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों के बीच-बचाव से मामला किसी तरह शांत हुआ।पीड़ित दुर्गा प्रसाद ने रविवार को करीब शाम 3 बजे पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।

### लम्बित व अदावी धनराशि नागरिकों को लौटाने हेतु ग्रामीण बैंक ने शुरू किया अभियान

**लालगंज।** आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत उ090 ग्रामीण बैंक ने लम्बित एवं अदावी धनराशि नागरिकों को लौटाने हेतु सभी सरकारी कार्यालयों से समन्वय व सहयोग की अपील की है। बैंक प्रबंधन ने भारत सरकार के इस जनहित अभियान के अन्तर्गत उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनपद के सभी संबंधित विभागों से सहयोग की अपेक्षा जतायी है। ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक आशुतोष चैव व उपक्षेत्रीय प्रबंधक रितुराज सिंह ने बताया कि अभियान जनहित से जुड़ा है। इसलिये विभाग आवश्यक अभिलेख, अधिकृत हस्ताक्षर तथा अन्य अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। जिससे की पात्र लाभार्थियों को उनकी धनराशि बिना किसी विलम्ब के प्राप्त हो सके।

## बजट सत्र में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम

### को पास कराए जाने की उठाई आवाज

### अखंड भारत संदेश

**प्रतापगढ़।** अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम विधेयक की मुहिम को लेकर आल इण्डिया रूरल बार एसोसिएसन के बैनरतलेरविवार को यहां बार कौन्सिल चुनाव के गहमागहमी के बीच अधिवक्ताओ ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। एसोसिएसन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल व महासचिव अनिल कुमार तिवारी के नेतृत्व में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम विधेयक को लेकर वकीलों की आम सभा भी हुई। आम सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने केंद्र सरकार के समक्ष यह मांग उठाई है कि सरकार का बजट पेश होने के बाद अब उसे अगला विधेयक मसदासचिव अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का लाना चाहिए।उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के बजट मे अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अलग से बजट न रखना अत्यंत निराशा जनक है। महासचिव अनिल



कुमार तिवारी ने कहा कि यदि सरकार इस सत्र में यह विधेयक पारित नहीं करती तो एसोसिएसन प्रदेशवासी आंदोलन तेज करेगा। आम सभा की अध्यक्षता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के पूर्व उपाध्यक्ष विष्णु पाण्डेय व संचालन प्रदेश प्रवक्ता विकास मिश्र ने किया।वकीलों ने अपनी मांग को लेकर नारे बाजी के साथ ज्ञानरूकता मार्च निकाला।बड़ी संख्या मे बार कौन्सिल के चुनाव को लेकर यहां जमा वकीलों ने भी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग

का समर्थन किया। जागरूकता मार्च का संयोजन प्रदेश महासचिव लवलेश शुक्ल ने किया। आम सभा को वरिष्ठ अधिवक्ता इमामुद्दीन, संजय ओझा ,राधवेन्द्र बहादुर सिंह, अनुग्रह प्रताप सिंह, सुभाष तिवारी, नवीउल्लाह, रणविजय सिंह, विपिन शुक्ल, राजेश तिवारी, संतोष पाण्डेय ने भी संबोधित किया। इस मौके पर अवरार अहमद, के.के. शुक्ला, मो.जैद, राकेश सेन, नफीस अली, हैदर अली, जितेन्द्र तिवारी, अरविन्द त्रिपाठीआदि अधिवक्ता रहे।

## गधियाँवा से प्रयागराज माघी कुंभ 2026

### के लिए नि:शुल्क भव्य बस सेवा संपन्न

**पट्टी।** माघी कुंभ 2026 के पावन अवसर पर ग्राम गधियाँवा से प्रयागराज संगम स्नान हेतु संचालित नि:शुल्क बस सेवा शनिवार को पूरी श्रद्धा, सेवा-भाव और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ भव्य रूप से संपन्न हुई। कड़क की ठंड और घने कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। सुबह करीब 7 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रद्धालु एकत्र हुए और संगम स्नान के लिए रवाना होकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकुशल वापस लौटे।इस पुनोत् सेवा का आयोजन दिनेश पांडेय, आलोक पांडेय एवं अविनाश पांडेय के नेतृत्व में किया गया, जबकि समस्त ग्रामवासियों ने निवेदक के रूप में सक्रिय सहभागिता निभाई। आयोजकों के कुशल नेतृत्व में पूरी



यात्रा व्यवस्था अनुशासित, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रही। नि:शुल्क बस सेवा ने विशेष रूप से ग्रामीण श्रद्धालुओं के लिए कुंभ स्नान को सुगम बनाया।यात्रा के आयोजक, समाजसेवी एवं भजन गायक दिनेश कुमार पांडेय ने कहा,माघी कुंभ केवल आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि यह सेवा और समर्पण का भी संगम है। गधियाँवा से प्रारंभ हुई यह नि:शुल्क बस सेवा समाज की

सामूहिक चेतना और सहयोग की भावना को दर्शाती है। ग्रामवासियों की सुविधाओं के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।ह्रदय आयोजन के निवेदक समस्त ग्रामवासी, गधियाँवा रहे। श्रद्धालुओं एवं ग्रामीणों ने इस सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त करके सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे समाजसेवा एवं सनातन परंपरा की प्रेरणादायी मिसाल बताया।



## कौशाम्बी संदेश

## उप मुख्यमंत्री ने ₹0-3181.08 लाख की लागत की 05 परियोजनाओं का किया शिलान्यास



उप मुख्यमंत्री ने ₹0-1608.78 लाख की लागत की 14 परियोजनाओं का किया लोकार्पण

**अखंड भारत संदेश**

**कौशांबी।** प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने डायट मैदान में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी, अयोध्या, बरेली व सहारनपुर में ₹0-13.39 करोड़ की लागत से निर्मित कॉमन इन्क्यूबेशन सेन्टरों का उद्घाटन/लोकार्पण किया, इस कार्यक्रम का जनपद-अयोध्या, बरेली व सहारनपुर में सजीव प्रसारण भी किया गया। उन्होंने विभिन्न विभागों/स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का फीता काटकर शुभारम्भ एवं स्टॉलों का अवलोकन के दौरान स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पाद की जानकारी प्राप्त करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया।उप मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास



योजानान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास खण्ड कड़ा में ₹0-3078.41 लाख की लागत की जिला ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना के लिए आवासीय/अनावासीय भवनों का शिलान्यास किया। इसी प्रकार उन्होंने पूर्वांचल विकास निधि योजानान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत नगर पंचायत सिराथू के हौलीपर में ₹0-49.98 लाख की लागत की विवाह घर हॉल, इण्टरलॉकिंग आदि कार्य का भी शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल विकास निधि

योजानान्तर्गत विकास खण्ड कड़ा के हुनमान घाट कड़ा धाम में ₹0-37.94 लाख की लागत से शव के अन्तिम संस्कार के लिए स्थल एवं आगनुको के लिए विश्राम/बैठने की उचित व्यवस्था का निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इसी प्रकार उन्होंने ₹0-18.97 लाख की लागत से संदीपन घाट कड़ा धाम में शव के अन्तिम संस्कार के लिए स्थल एवं आगनुकों के विश्राम/बैठने की उचित व्यवस्था का निर्माण कार्य, ₹0-28.40 लाख की लागत से सिराथू

## उप मुख्यमंत्री ने जिला उद्यान कार्यालय परिसर में ₹0-339.10 लाख की लागत से निर्मित कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर का किया लोकार्पण

उप मुख्यमंत्री ने सरस हाट का शुभारम्भ कर स्वयं सहायता समूहों को दुकानों का किया आवंटन

**कौशांबी।** प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय परिसर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजानान्तर्गत ₹0-339.10 लाख की लागत से निर्मित कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर का उद्घाटन/लोकार्पण किया। उन्होंने ब्लॉक परिसर मंझनपुर में सरस हाट का शुभारम्भ कर स्वयं सहायता समूहों-रानी महिला स्वयं सहायता समूह, शारदा महिला स्वयं सहायता समूह, गौरी महिला स्वयं सहायता समूह, चारिका महिला स्वयं सहायता समूह, नारी शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह, शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह एवं राधे महिला स्वयं सहायता समूह सहित कुल 20 स्वयं सहायता समूहों को दुकानों का आवंटन किया।



पंचायत दारा नगर में तीर्थ यात्रियों के विश्रामालय तक सम्यक् मार्ग में इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य, ₹0-22.32 लाख की लागत से पंचायत दारानगर में तीर्थ यात्रियों के विश्रामालय में जनसुविधा के लिए सामुदायिक शौचालय, स्नानागार/सबमर्सिबल पम्प का निर्माण कार्य, ₹0-49.98 लाख की लागत से नगर

पालिका परिषद मंझनपुर के अन्तर्गत कोरों में पुस्तकालय/ अध्ययन संस्थान का निर्माण कार्य एवं ₹0-43.32 लाख की लागत से नगर पालिका परिषद मंझनपुर के अन्तर्गत कोरों में पुस्तकालय एवं अध्ययन संस्थान में शौचालय, इण्टरलॉकिंग/ वाटर शेड समर्सिबल पम्प का निर्माण कार्य का लोकार्पण किया।

## उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डमी चेक/ट्राई साइकिल/स्वीकृत प्रमाण-पत्र/आवास की चाभी किया प्रदान

**अखंड भारत संदेश**

**कौशांबी।** प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने डायट मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के लाभार्थियों-राजकुमार कैथवास को 11 लाख ऋण, पवन कुमार साहू को 10 लाख ऋण एवं नीलम तिवारी को 07 लाख ऋण का डमी चेक प्रदान किया। इसी प्रकार उन्होंने सी.एम. युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों को ₹0-05 लाख ऋण का डमी चेक तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 171 स्वयं सहायता समूहों को केश क्रेडिट लिंकेज के लिए ₹0-51.30 लाख की सहायता राशि का डमी चेक, 221 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के लिए 3.31 करोड़ की सहायता राशि का डमी चेक व 2306 स्वयं सहायता समूहों को केश क्रेडिट लिंकेज के लिए ₹0-34.59 करोड़ की सहायता राशि का डमी चेक प्रदान किया। उन्होंने मत्स्य विभाग के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र/प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्होंने दिव्यांगजन को ट्राई साइकिल प्रदान किया।उप मुख्यमंत्री ने कृषि यन्त्रीकरण योजना के लाभार्थी-पारसनाथ को ₹0-34 लाख अनुदान का डमी चेक व ओम प्रकाश को ट्रैक्टर की चाभी प्रदान किया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)/प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को आवास की चाभी प्रदान किया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को

उप मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कामिकों को प्रशस्ति-पत्र एवं छात्र-छात्राओं को शिक्षण सामग्री किया प्रदान

## मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का उप मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण

**कौशांबी** प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंझनपुर में आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध जाँच की जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने मरीजों से वार्ता कर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाय।

स्वीकृत पत्र, वाद्ययन्त्र योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को वाद्ययन्त्र प्रदान किया। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय व कस्तूरबा गांधी अवासीय बालिका विद्यालयों की छात्र-छात्राओं को शिक्षण सामग्री प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने पी.एम.एफ.एम.ई. योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैकर्स-नवीन कुमार झाँ, भीम सिंह, अजय सिंह व मुंकेश कुमार को प्रशस्ति-पत्र एवं लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया।

## सरकारी जमीन पर कब्जे को रोकने के गए ग्रामीणों पर हुआ हमला

**अखंड भारत संदेश**

**कौशांबी।** मंझनपुर तहसील क्षेत्र के नगर पालिका मंझनपुर के ओसा ग्राम पंचायत में सरकारी आराजी संख्या 2652 ख में गांव के शिव कुमार पुत्र शिव मंगल आदि लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है गांव की मालती देवी सहित तमाम लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जे को रोकना तो शिवकुमार सहित दर्जनों लोगों ने लाठी डंडा लेकर ग्रामीणों का दौड़ा लिया है ग्रामीणों ने भाग कर जान बचाई है इसी सरकारी जमीन पर पंचायत भवन बना हुआ है इसी सरकारी जमीन पर देवस्थान बना हुआ है इसी सरकारी जमीन पर गांव के किसानों की फसल का खलिहान है जहाँ किसान फसल रखते हैं सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर के तहसील प्रशासन और पुलिस गंभीर नहीं है ग्रामीण सरकारी



जमीन के कब्जे को रोक रहे हैं तो ग्रामीणों पर हमले हो रहे हैं मामले की सूचना मालती देवी माया देवी नाथन लाल रामराज सुर्जन अर्जुन राममिलन सूरज कली अजय कुमार अशोक कुमार अरविंद कुमार मीरा देवी अनोता देवी सहित तीन दर्जन

लोग एसडीएम और डीएम की चौखट पर पहुंचे हैं और शिकायती पत्र देकर सरकारी जमीन पर कब्जे को रोकने की मांग की है सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने के मामले में संबंधित लेखपाल की भूमिका पर सवाल खड़े हैं।

## पत्नी की बेवफाई से तस्त्त युवक ने पुलिस से लगाई गुहार

**अझुवा कौशाम्बी** सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक युवक ने पत्नी के बेवफाई से आजिज होकर पुलिस से ईसाफ की गुहार लगाई है।एक युवक ने अझुवा चौकी पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया 2 वर्ष पहले रोजी रोटी कमाने पत्नी के साथ सूरत शहर गया था वहां उसकी पत्नी के लोकल युवक से नाजायज संबंध हो गए पूछने पर झगड़ा करने लगी, युवक तैयार होकर ससुराल आने लगा उसके साथ उसकी बीवी और बच्चे भी ससुराल आ गई ससुरालियों को जानकारी देने पर गाली गलौज करते हुए उसका बैग रखवा लिया गया युवक ज्योंहि अपने पुरवा पहुंचा पीछे से उसकी पत्नी भी पहुंच गई युवक के आरोपों के अनुसार उसकी पत्नी झूठे मुकदमे में फंसने और जान से मारने की धमकी देती है वही चौकी पुलिस तहरीर लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है।

## सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

**कौशांबी** पिपरी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के करन उम्र 28 वर्ष पुत्र रामरूप 25 जनवरी को चरवा थाना क्षेत्र के जानकीपुर के पास सड़क किनारे पैदल जा रहे थे किसी वाहन की टक्कर से वह गंभीर घायल हो गए इलाज के लिए अस्पताल में भती कराया गया था जहां इलाज के दौरान शनिवार की रात उसकी मौत हो गई।युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।बेटे के मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके निधन से पत्नी कविता और बच्चे रो-रोकर बेहाल हैं।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया एक सप्ताह बीत जाने के बाद अभी तक थाना पुलिस ने दुर्घटना करने वाले वाहन की तलाश नहीं की है जिससे पुलिसिया लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है।

## माफियाओं ने काट डाले आधा दर्जन हरे फलदार पेड़

**अखंड भारत संदेश**

**कौशांबी** चायल सर्किल क्षेत्र के चरवा थानान्तर्गत सैयद सरावां पुलिस चौकी के कूड़ापुर गांव की एक बाग मे लकड़ी माफिया ने हरे फलदार आधा दर्जन से अधिक पेड़ को पेद्रोलिंग आराम मशीन से शनिवार की रात को काट दिया है और बेखौफ तरीके से वाहनों में भरकर बिना ट्रांजिट परमिट के हरे पेड़ की लकड़ी भी उठा ले गए हैं जिले में कहीं ना कहीं प्रतिदिन हरे पेड़ काटे जा रहे हैं लकड़ी माफिया बेखौफ है वन विभाग से लेकर पुलिस तक हरे पेड़ की कटान पर रोक नहीं लगा रही बल्कि हरे फलदार पेड़ों को काटने का परमिट वन विभाग द्वारा माफिया को जारी कर दिया जाता है जिससे माफिया हरे पेड़ को



काटकर धरती को वीरान बना रहे हैं मामले की शिकायत टिवटर के माध्यम से भी शासन प्रशासन तक हुई लेकिन उसके बाद भी माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई हरे पेड़ को वन विभाग के अधिकारी कटने से रोक नहीं सके हैं जिससे पूरी वन विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़े हैं यदि चर्चाओं पर

जाए तो जनवरी महीने में कौशांबी के अलग-अलग क्षेत्र में हजारों हरे फलदार पेड़ काटे गए हैं सवाल उठता है कि हरे फलदार पेड़ों की सुरक्षा के लिए वन विभाग में अफसर की तैनाती की गई है या फिर हरे फलदार पेड़ को कटवाने के लिए वन विभाग में अफसर को तैनात किया गया है।

## न्यूज झरोखा

## कई वर्षों से बंद पड़ा सामुदायिक शौचालय, वार्ड वासी खुले में शौच को मजबूर



**अझुवा कौशाम्बी** आदर्श नगर पंचायत अझुवा वार्ड नंबर दो अंबेडकर नगर में स्थित सामुदायिक शौचालय में वर्षों से ताला बंद है जिससे वार्ड वासी खुले में शौच जाने को मजबूर है वार्ड वासियों का कहना है की शौचालय निर्माण के बाद से ही इसमें ताला लगा हुआ है जिससे दरवाजे ताला में भी जंग लग गया वार्ड वासी शोखर और अन्य वार्ड वासियों ने बताया इस सामुदायिक शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है शौचालय के अंदर का टाइल्स सीट टूट गया है शौचालय की स्थिति अत्यंत खराब है वार्ड वासियों के अनुसार यह शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2017-18 में बनाया गया था नगर पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों की लागत से बना सामुदायिक शौचालय निर्माण के 8 साल बाद भी बंद पड़ा है, पानी, बिजली और रखरखाव के अभाव में यह बेकार पड़ा है, जिससे ग्रामीण आज भी खुले में शौच को मजबूर हैं,जिम्मेदार की लापरवाही के कारण ताला नहीं खुला है. लेकिन जिम्मेदारों के लापरवाही और नगर पंचायत के जिम्मेदार की मिली भगत के कारण इसका लाभ किसी को नहीं मिल सका है



**कौशांबी।** संत शिरोमणि रविदास की जन्मजयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर रविवार को जिलाध्यक्ष कांग्रेस गौरव पाण्डेय के निर्देशानुसार कड़े में उनकी छायाचित्र पर माल्यार्पण करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संत रविदास 15वीं-16वीं शताब्दी के महान भारतीय भक्ति संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिन्होंने जातिवाद के घोर विरोध और समानता का संदेश दिया। वे वाराणसी के चमकौर समुदाय से थे और निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। उनके पद और साहित्यीय ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। "मन चंगा तो कलौती में गंगा" का प्रसिद्ध कथन उन्ही का है। इसके बाद इंद्रपाल रैदास ने बताया कि महान संत गुरु रविदास जी 15वीं शताब्दी के महान संत,समाज सुधारक और कवि थे। संत रविदास ने समाज में फैली बुराईयों को जड़ से समाप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। संत रविदास लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहते थे। उनका मानना ​​था कि ईश्वर के बनाए हर व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब सब एक समान ही हैं।

## अमीरों को अमीर करने वाला बजट आम जनता के लिए इस बजट में कुछ नहीं :स गौरव पाण्डेय

**कौशांबी** संसद भवन में भाजपा सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा रविवार को पेश किए बजट पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव पाण्डेय ने कहा कि अमीरों के काम-कारोबार और घूमने-फिरने पर दस तरह की छूट दी गई है लेकिन बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की उम्मीदों की थाली,खाली है।-।मध्यम वर्ग अपने को ठगा महसूस कर रहा है।शोषित, वंचित, गरीब व्यक्ति जहाँ था उससे भी नीचे जाता दिख रहा है। क्योंकि सामाजिक सुरक्षा शाब्दिक औपचारिकता तक सीमित होकर रह गयी है किसान,मजदूर श्रमिक कारोबारी,छोटा दुकानदार अपने लिए मिली राहत को दूरबीन लेकर भी ढूँढ नहीं पा रहा है।



## यौन उत्पीडन का मुकदमा दर्ज आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

**अझुवा कौशाम्बी** सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 2 जनवरी को तालाब की तर्फ शौच किया करने गई 3 बच्चों की मां के साथ चाकू दिखाकर एक वहशी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया,शोर मचाने पर चाकू दिखाते हुए हत्या की धमकी दी जिससे महिला डर गई।रोजी रोटी के सिलसिले में मानिक पुर से 26 जनवरी को आए पति से महिला ने अपनी आप बीती बताया।महिला के अनुसार उसके मोबाइल नंबर में दुष्कमी बराबर फोन कर घटना की कही भी शिकायत करने पर बच्चों और पति की हत्या की धमकी देता रहा जिससे महिला डर गई थी। महिला की तहरीर पर सैनी कोतवाली पुलिस ने प्रमोद पुत्र शंभू के खिलाफ दुष्कर्म सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश में जुट गई है।

## घर से भागे दो नाबालिग बालकों को पुलिस ने किया बरामद

**कौशांबी।** संदीपनघाट थाना क्षेत्र के बसेड़ी गांव से 11 जनवरी को प्रवीण सिंह के 15 वर्ष का बेटा अपने बगल में रहने वाले 15 वषीय दोस्त के साथ घर से कोचिंग जाने की बात कहकर गए थे, परन्तु वापस नहीं आए संदीपनघाट थाना में अभियोग पंजीकृत हुआ दिनांक 01.02.2026 को थाना संदीपनघाट पुलिस ने इमामगंज तिराह के पास से उपरोक्त गुमशुदा दोनो बालकों को बरामद किया है पूछताछ में बच्चों द्वारा बताया गया कि घरवालों से नाराज होकर चले गये थे बरामद बच्चों को बाल कल्याण समिति के समाज प्रस्तुत कर नियमानुसार कायदावीही की जा रही है।



# सम्पादकीय

# मोदी- दोनों हाथों में लड्डू

**जसा** कि अनुमान लगाया जा रहा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए चाहे जितने कठोर नियम बना ले, उन्हें लागू करना आसान नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ भी। यूजीसी द्वारा जारी नए नियमों पर देश भर में सवाल और बवाल दोनों खड़े हुए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने के लिए याचिकाएं दायर हुईं, जिन पर गुरुवार 29 जनवरी को महत्वपूर्ण सुनवाई भी हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अस्थायी रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पहले दृष्टिकोण से यह प्रतीत होता है कि इन नियमों की भाषा में स्पष्टता की कमी है, जिससे उनका गलत उपयोग हो रहा हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश च्यवन ने चेतावनी दी कि ऐसे नियमों को लागू करने से समाज को विभाजित कर सकते हैं और परिसरों में अमेरिका की तरह नस्लबर्ही विभाजन जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन नियमों की जांच की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका उपयोग न हो। कोर्ट ने केस सरकार से इन नियमों की समीक्षा करने को कहा और तब तक उनके लागू होने पर रोक जमा रखने का आदेश दिया। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वे एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करें। जिसमें कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करने पर विचार किया जाए, ताकि समाज में न्याय के बिना भेदभाव के समग्र विकास हो सके। गौरलतब है कि यूजीसी की नियमानुवली, 2026 को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था। ये नियम अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) छात्रों के खिलाफ भेदभाव, उत्पीड़न और आतंकवादी जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लागू हुए हैं। यह 2012 के पुराने नियमों की जगह लाए गए हैं। इन नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में समता समितियाँ (डिविटी कमेटी) गठित करना अनिवार्य किया गया है। इस कमेटी का काम जातिगत भेदभाव की शिकायतों की जांच करना है। लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी के हक की बात उठते ही समाज में बवाल खड़ा हो गया। भारत में जाति व्यवस्था इतनी गहरी पैठी हुई है कि जाति के नाम पर उत्पीड़न सामान्य व्यवहार के तौर पर अपना लिया गया है। एक ईंसान दूसरे ईंसान को केवल जाति के आधार पर अपमानित, शोषित या प्रताड़ित करे, शोषण करने सदियों से चला आ रहा है और इसे दूर करने की जितनी कोशिश की गई, उतने ज्यादा अड़गे सवर्ण समाज की तरफ से लगाए गए। चाहे मंडल कमीशन की सिफारिशें हो या अभी यूजीसी के नए नियम, उन पर समाज का एक तबका ऐसे विरोध में उतरा माने अपने से निचली जातियों का उत्पीड़न उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण वर्ग की ओर से दायर याचिकाओं में इन नियमों को असंवैधानिक बताया गया है। इसे जाति आधारित भेदभाव कारा दिया। याचिकाकर्ताओं में से एक वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमारे भेदभाव सिद्धान्त के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है और इससे शिक्षा क्षेत्र में, समाज में और अधिक खाई पैदा हो सकती है। कितने कमाल की बात है कि शिक्षा क्षेत्र या समाज में जातिगत भेदभाव इन लोगों को तब दिखाई नहीं देता, जब किसी दलित बच्चों को मध्याह्न भोजन में अलग पक में बिठाते की खबरें आती हैं।

# शिक्षा में समता या नई असमानता: यूजीसी नियमों पर न्यायिक विराम

-ललित गर्ग-

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के नाम पर लागू किए गए नए नियमों ने देश के शैक्षिक और सामाजिक परिदृश्य में एक बार फिर गहरी हलचल पैदा कर दी है। जिस नीति को ह्रस्वमाताह्र, ह्रस्वमान अवसरह्र और ह्रस्वमावेशी शिक्षाह्र की भावना से जोड़कर प्रस्तुत किया गया, वह व्यवहार में आते ही एक वर्ग विशेष के तीव्र विरोध, व्यापक असंतोष और सामाजिक तनाव का कारण बन गई। स्थिति इतनी विकट हुई कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर इन नियमों पर अंतिम रोक लगानी पड़ी। यह रोक न केवल सरकार की नीति-निर्माण प्रक्रिया पर एक प्रश्नचिह्न है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिशयोक्तिपूर्ण और असंतुलित प्रयोग देश को किस दिशा में ले जा सकता है।

प्रमोद कोर्ट का यह हस्तक्षेप किसी नीति के समर्थन या विरोध का सीधा निर्णय नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक चेतावनी है कि समानता के नाम पर लागू किए गए नियम यदि अस्पष्ट हों, दुरुपयोग की संभावना रखते हों और सामाजिक सोहार्द की समीक्षा से परे नहीं रह सकते। अदालत ने प्रथम दृष्टया यह माना कि यूजीसी के नए नियमों में स्पष्टता का अभाव है और यही अस्पष्टता उन्हें विवादस्पद बनाती है। यह लोक सरकार की आत्ममंथन का अवसर देती है। एक ऐसा अवसर जिसे राजनीतिक टकराव के बजाय सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि जो सरकार बार-बार ह्रस्वका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासह्व की

**तक : भविष्य**



से सस्ती और उसका सीधा मांग बढ़ने से -तीनों को गति में प्रत्यक्ष नकद और शिक्षा पर सुजन के ठोस ने कार्यक्रमों का लिए भी समान संगठित क्षेत्र के सुरक्षा इस दिशा है।

क और प्रमुख से शहरीकरण शहरों पर जल, स्वच्छता भार बढ़ रहा है। निर्भरता अब बैंक के अध्यक्ष गया शहरी न के संदर्भ में न मध्यम शहरों के केंद्र बनाना, वहां प्रोत्साहित करना, न केवल महान करंगा बल्कि क्षेत्रीय घटाएगा। बजट में यदि 3 शहरों के लिए विशेष पैकेज, परिवहन ने कनेक्टिविटी और कौशल लाई जाती हैं, तो यह आधार बन सकता है। वैसिक स्तर पर टैरिफ, संरक्षणवाद की प्रवृत्ति चुनौती भी हैं और अवि का यह कथन कि टैरिफ करने के बजाय व्यापार दिया जाना चाहिए, भारत के लिए उपयुक्त दृष्टि पर के पास विशाल घंटा जनसंख्या, डिजिटल उद्यमशीलता की प्रबल बजट निर्यात-उन्मुख उ मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू प्रोत्साहन देता है, तो भारत श्रमिक इन ईडिआह भारतहू को केवल नारा

बात करती रही है, वह शिक्षा संस्थानों जैसे विचार-निर्माण के केंद्रों में ऐसे नियामक कार्यों लाई, जिनसे जातिगत पहचान और वर्गीय विभाजन की रेखाएँ और गहरी होनी को आशंका पैदा हो गई। भारत का सामाजिक इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि जाति के नाम पर की गई किसी भी नीति ने, चाहे उसका उद्देश्य कितना ही कल्याणकारी क्यों न रहा हो, समाज को भीतर ही भीतर विभाजित किया है। आरक्षण जैसी सैद्धांतिक व्यवस्था सामाजिक न्याय के लिए लाई गई थी, लेकिन इसके लंबे प्रयोग ने देश को ऐसे घाव भी दिए हैं, जिनका उपचार आज तक पूर्ण रूप से नहीं हो सका। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में जातिगत आधार को और उधारने वाली किसी भी पहल को लेकर स्वाभाविक रूप से आशंका उत्पन्न होती है।

शिक्षा संस्थान केवल डिग्री बांटने की पैकट्रयि नहीं होते; वे समाज की दिशाशाही फैलाने के लिये तैयार होने वाला छात्र केवल नैतिकरिषा व्यक्त नहीं हैं, बल्कि भविष्य का नागरिक होता है। यदि यही परिसर शांति, अवश्रवास, वर्ग-संघर्ष और परस्पर शंका के केन्द्र बन जाएं, तो इसका प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वहाँ समाजिक ताने-बाने की भी कमजोरकराती है। यूसीसी के नए नियमों की लेकर उठा विरोध इसी आशंका का प्रकटीकरण है। यह भी विचारणीय है कि समानता नहीं और समता के बीच का अंतर नीति-निर्माण में किस हद तक समझा गया। समानता का अर्थ है सबके साथ एक-एकसा व्यवहार, जबकि समता का अर्थ है परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समुचित अनुचित अवसर देना। यदि समता के नाम पर ऐसे प्रावधान किए जाएं जो एक नए



प्रकार की असमानता को जन्म दे, तो वह नीति अपने उद्देश्य से भटक जाती है। सुप्रिम् कोर्ट की टिप्पणी इसी बिंदु की ओर संकेत करती है कि नियमों का उद्देश्य भरोसा ही सकारात्मक रहा हो, लेकिन उनकी संरचना और भाषा ने विवाद और भ्रम को जन्म दिया।

यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग तेजी से हावी होता गया। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इसे अपने-अपने हित के चश्मे से देखना शुरू कर दिया, वोट बैंक की राजनीति से इसे देखा जाने लगा जबकि यह विषय मूलतः शिक्षा सुधार और सामाजिक संतुलन से जुड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कई अवसरों पर यह कहते रहे हैं कि शिक्षा को राजनीति से मुक्त रखा जाना चाहिए और नीतियां दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर बननी चाहिए। फिर यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि यजीजी

द्वारा बनाए गए इन नियमों में उस  
 दृष्टिगत और संतुलन का अभाव क्यों  
 दिखा ? लगता है कि यूजीसी ने जल्दबाजी  
 में बिना सोचे समझे इसे लागू कर  
 दिया, यदि यूजीसी ने व्यापक संवाद, सभी  
 पक्षों से परामर्श और संभावित दुरुयोगों  
 की आशंकाओं का पूर्व आकलन किया  
 होता, तो शायद यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं  
 होती। नीति बनाते समय केवल कानूनी  
 वैधता पर्याप्त नहीं होती; सामाजिक  
 स्वीकार्यता और नैतिक संतुलन भी उतने  
 ही आवश्यक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने  
 अपने आदेश के माध्यम से यही संकेत  
 दिया है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में  
 किसी भी बदलाव से पहले उसके दूरगामी  
 प्रभावों पर गंभीरता से विचार किया जाना  
 चाहिए।  
 नए नियमों की सबसे बड़ी कमजोरी एव  
 त्रासदी यही रही कि वे आरक्षित और  
 सामान्य वर्गों को एक-दूसरे के सामने

बुझा करके विद्रोह एवं विरोध में खड़ा कर दिया। यह विभाजनकारी प्रवृत्ति न केवल शिक्षा के वातावरण को दूषित करती है, बल्कि उस राष्ट्रीय एकता की अवधारणा को भी कमजोर करती है, जिसको बात हम संविधान में करते हैं कि किसी भी नीति का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह समाज को जोड़ती है या तोड़ती है। यदि यह अविश्वास और टकराव को बढ़ावा देती है, तो उस पर पुर्नविचार अनिवार्य हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक सुधार का अवसर है—सरकार, यूजीसी और समूचे शैक्षिक तंत्र के लिए। यह समय है कि भावनाओं और राजनीतिक आग्रहों से ऊपर उठकर एक ऐसी नीति बनाई जाए, जो वास्तव में समान अवसर सुनिश्चित करे, लेकिन बिना किसी नए विभाजन को जन्म दिया। शिक्षा में सुधार का अर्थ समाज को आगे ले जाना है, न कि पुराने घावों को फिर से करेदना।

देश को ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जो प्रतिभा को जाति से ऊपर रखे, अवसर को पहचान से मुक्त करे और परिसरों को संघर्ष का नहीं, संवाद का केंद्र बनाए। सुप्रीम कोर्ट की यह रोक उसी दिशा में एक संकेत है। अब यह सरकार और यूजीसी की जिम्मेदारी है कि वे इस संकेत को समझे, आत्मावलोकन करें और ऐसे नियम गढ़ें जो वास्तव में भारत की समावेशी, संतुलित और भविष्यदर्श संचरणा के अनुरूप हों। यदि इस अवसर को भी राजनैतिक स्वार्थ की भेंट चढ़ा दिया गया, तो यह केवल एक नीति की विफलता नहीं होगी, बल्कि उस विश्वास की भी हार होगी, जो जनता ने शिक्षा सुधारों से जोड़ रखा है।

## आर्थिक सर्वेक्षण से बजट तक : भविष्य के भारत की तलाश

-: ललित गर्ग :-

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद के पलट पर प्रस्तुत किया जाने वाला बजट केवल आय-व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा नहीं होता, बल्कि वह देश की आर्थिक दिशा, सामाजिक प्राथमिकताओं और भविष्य की संभावनाओं का दर्पण होता है। आज जब भारत एक ओर तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व मंच पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है और दूसरी ओर वैश्विक अनिश्चितताओं, भू-राजनैतिक तनावों, जलवायु संकट और तकनीकी परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब यह बजट और भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। व्यक्तिगत नागरिक से लेकर व्यापारी, उद्योगपति, किसान, श्रमिक, युवा और मध्यम वर्ग-सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हैं, क्योंकि इसमें न केवल वर्तमान वर्ष की आर्थिक तस्वीर, बल्कि भूभविष्य के भारतहू की झलक भी मिलती है।

बजट से पूर्व प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण ने सरकार की सोच और नीति-दृष्टि के कई संकेत दिए हैं। इसमें विकास को केवल आंकड़ों की वृद्धि तक सीमित न रखकर अवसरों के विस्तार, समावेशी विकास और दीर्घकालिक स्थिरता पर जोर दिया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियाँ अवश्य हैं, किंतु उनसे अधिक संभावनाएं हैं। यही दृष्टिकोण इस बजट का मूल स्वर होना चाहिए-चुनौतियों को अवसरों में बदलने का साहसिक प्रयास।



नागरिक से लेकर व्यापारी, उद्योगपति, किसान, श्रमिक, युवा और मध्यम वर्ग-सभी की निगाहें सब जगह पर टिकी हैं, क्योंकि इससे न केवल वर्तमान वर्ष की आर्थिक तस्वीर, बल्कि ह्रस्वविषय के भारतह्व का झलक भी मिलती है।

बजट से पूर्व प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण ने सरकार की सोच और नीति-दृष्टि के कई संकेत दिए हैं। इसमें विकास को केवल आंकड़ों की वृद्धि तक सीमित न रखकर अवसरों के विस्तार, समावेशी विकास और दीर्घकालिक स्थिरता पर जोर दिया गया है। वह स्वीकार किया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियाँ अवश्य हैं, किंतु उनसे अजकक संभावनाएँ हैं। यही दृष्टिकोण इस बजट का मूल स्वर होना चाहिए-चुनौतियों को अवसरों में बदलने का साहसिक प्रयास।

सबसे पहली और महत्वपूर्ण अपेक्षा निम्न वर्ग की क़दम-शक्ति बढ़ाने को लेकर है। किसी भी अर्थव्यवस्था की वास्तविक मजबूती तभी आती है जब उसके सबसे निचले पायदान पर खुदा व्यक्ति भी सम्मानजनक जीवन जी सके और उपभोग में भागीदार बने। यही निम्न आ

## 649वीं रविदास जयंती पर मुहम्मदाबाद यूसुफपुर में भव्य शोभा यात्रा, भक्तिरस में सराबोर हुआ नगर

अखंड भारत संदेश  
गाजीपुर। जनपद के नगर व  
ग्रामीण क्षेत्रों में संत शिरोमणि  
रविदास जी की जयंती धूमधाम से  
मनाई गई।

49वीं संत शिरामणि गुरु रविदास और गगनभैरव जयंती के पानन अवसर गगनभैरव स्थानीय थाना कोतवाली अंतर्गत उठा। पानन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धा जयघोष उत्साह और भक्तिभाव से ओत-प्रोत जी के श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा का आयोजन और पट्टे चाल किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर नगर सहित आसपास के ग्रामीण नगर एवं श्रद्धालु क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु निकल जलूस के रूप में शोभा यात्रा में अपनी

सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा में संत रविदास जी की आकर्षक और सुसज्जित झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। झांकी के दर्शन कर भक्त भाव-विभोर हो उठे और ह्रस्व रविदास की जयह्व के गगनभेदी जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंज उठा। भक्तों ने भजन-कीर्तन और जयघोष के माध्यम से संत रविदास जी के संदेश-समता, प्रेम, भाईचारा और मानवता—को जन-जन तक पहुंचाया।

नगर के स्टेट बैंक हरिजन बस्ती से निकली शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने अपनी कला-कौशल का अद्भुत

प्रदर्शन किया। पारंपरिक वेशभूषा, डोल-नगाड़ों की मधुर धुन, नृत्य और भक्ति गीतों ने शोभा यात्रा को और भी भव्य बना दिया। बच्चे, युवा, महिलाएँ और बुजुर्ग—सभी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ इस सावन आयोजन में सहभागी बने।

शांथा यात्रा नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों और क्षेत्रों से होती हुई आगे बढ़ी, जहाँ जगह-जगह पुष्पवर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। आयोजन को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के



लिए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ शोभा यात्रा के साथ-साथ चलता रहा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था घाक-चौबंद बनी रही।

कुल मिलाकर, 649वीं रविदास जयंती के अवसर पर निकाली गई यह शोभा यात्रा न केवल धार्मिक

आस्था का प्रतीक बनी, बल्कि संत  
रविदास जी के आदर्शों को  
आत्मसात करने का संदेश भी देती  
नजर आई। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र  
भक्तिरस में डूबा रहा और यह  
पावन पर्व श्रद्धा, शांति और सौहार्द  
के साथ संपन्न हुआ।

निलेश देसाई

एक कड़वी सच्चाई आज का भारतीय किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ खेती में 'प्रचलन बेरोजगारी' का शोर है, तो दूसरी तरफ हकीकत यह है कि बुवाई और कटाई के लिए सीजन में किसान को एक मजदूर तक नसीब नहीं होता। जो मजदूर उपलब्ध हैं उनको नकद मजदूरी की मांग और किसान की भुगतान करने की घटती क्षमता। परिणामस्वरूप के बीच फंसी खेती भारतीय कृषि आज एक अजीबोगरीब चोराहे पर खड़ी है। अर्थशास्त्री इसे 'अधिशेष श्रम' का श्रेण कर रहे हैं, जहाँ आसपास तथा से अधिक लोग नियोजित हैं। लेकिन धरतल की सच्चाई इसके ठीक उल्टा है। आज गांव का किसान बुवाई और कटाई के महत्वपूर्ण समय में 'हाथ' तलाश रहा है, जबकि खेत में पसीना बहाने वाला मजदूर सम्मानजनक पारिश्रमिक और सुरक्षा के अभाव में शहरों की ओर पलायन कर रहा है। यह केवल एक आर्थिक संकट नहीं है बल्कि उस सामाजिक ढाँचे का ढहना है जिसने सदियों तक भारतीय गांवों को आत्मनिर्भर बनाए रखा था। इस गहराते संकट के बीच, मध्य प्रदेश के झांझा आ की आदिवासी परंपरा 'अड़जी-पड़जी' एक ऐसी मशाल बनकर उभरती है, जो न केवल श्रम की समस्या का समाधान देती है, बल्कि आधुनिक खेती के लिए एक नया 'इकानॉमिक मॉडल' भी प्रस्तुत करती है।

कृषि श्रम का गहराता संकेत : एक कड़वी सच्चाई आज का भारतीय किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ खेती में 'प्रच्यन बेरोजगारी' का शोर है, तो दूसरी तरफ हकीकत यह है कि बुवाई और कटाई के पीछे सीजन में किसान को एक मजदूर तक नसीब नहीं होता। जो मजदूर उपलब्ध हैं, उनको नकद मजदूरी की मांग और किसान की भुगतान करने की घटती क्षमता के बीच एक गहरा खाई पैदा हो रहा है। अड़जी-पड़जी सामूहिक श्रम की गौरवशाली परंपरा: जहां अधुनिक नीतियां विफल होती हैं, वहां आदिवासी समाज का 'स्थानीय ज्ञान' मार्ग अखिलांतर है। झाबुआ और अलीराजपुर के आदिवासी अंगुलों में प्रचलित 'अड़जी-पड़जी' कोई साधारण प्रथा नहीं, बल्कि श्रम के कोलैक्टरीकरण का उक्तुष्ट उदाहरण है। 'अड़जी-पड़जी' का दर्शन



खरल और प्रभावी है: इसमें गांव के किसान एक-दूसरे के खेतों में सामूहिक रूप से काम करते हैं। यदि आज एक किसान के खेत में बीज रोपना है, तो पूरा गांव या टोला वहां मौजूद होगा। कल वहीं एक-दूसरे के खेतों में जाएगा। वहां श्रम का मूल्य 'नोटों' में नहीं, बल्कि 'सहयोग' में मापा जाता है। इसमें न कोई मालिक है, न कोई नौकर; हर कोई एक-दूसरे का सहयोगी है।

समाधान के रूप में स्थानीय ज्ञान के लाभ: अड़जी-पड़जी जैसी हरंपरंपरा आधुनिक कृषि की तीन बड़ी चुनौतियों का समाधान करती हैं- आर्थिक स्वावलंबन, छोटे और नकद सीमांत किसानों के पास नकद राशि का अभाव होता है। अड़जी-पड़जी नकद मजदूरी की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, जिससे किसान को साहूकार या बैंकों से कर्ज नहीं लेना पड़ता।

अभयबद्धता और लचीलापन: कृषि में समय का बहुत महत्व है। बारिश होने के साथ ही बुवाई शुरू करनी होती है। अड़ड़ो-पुड़ड़ो के माध्यम से जो काम एक परिवार दस दिनों में करता, वह समूहिक जगत से एक ही दिन में सम्पन्न हो जाता है।

श्रम की गरिमा और सुरक्षा: जब किसान एक-दूसरे के खेतों में काम करते हैं, तो काम में 'सम्मान' जुड़ जाता है। यह उन मजदूरों के लिए भी एक सुरक्षित विकल्प है जो शहरों की अत्युरक्षित गलियों में धक्के खाने के बजाय अपने समुदाय के बीच रहकर गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं।

कृषि श्रम को परंपरा को नीति का समर्थन: झाबुआ के इस अनुभव को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए केवल सराहना काफी नहीं है, इसे नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। एक 'कृषि श्रम कोष' की स्थापना समय की मांग है। इस कोष का उद्देश्य उन समुदायों और समूहों को वित्तीय प्रोत्साहन देना होगा जिन्होंने कृषि मशीनीकरण के बजाय

परंपरिक श्रम-साझा प्रणालियों को चुनते हैं। यह कोष छोटे और मध्यम किसानों को संगठित होने, 'दुल बैक' (साझा कृषि उपकरण) बनाने और पीक सीजन के दौरान होने वाले जोखिमों को कम करने में मदद कर सकता है। यदि सरकार मनरेगा जैसी योजनाओं को इस स्थानीय श्रम-साझा मॉडलों के सपोर्ट जोड़ दे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उत्पादकता दोनों में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है।

परिस्थितिकी और सामाजिक न्याय का संगम: अड़जी-पड़जी केवल श्रम बचत का तरीका नहीं है। 'प्राकृतिक खेती' का आधार भी है। जब श्रम सामूहिक होता है, तो रसायनों की जगह हाथों से निराई गुड़ाई संभव होती है। इससे मिट्टी की उर्वरता बचती है और पर्यावरण की रक्षा होती है। यह मॉडल सामाजिक न्याय की भी बात करता है, क्योंकि यह महिलाओं के क्रमशः अधिक होने से बचाता है और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करता है।

जड़ों की ओर वापसी: भारतीय किसान कृषि आज जिस चौराहे पर खड़ी है, वहां रास्ता केवल 'स्मार्ट सिटी' या 'बढ़ी मशीनों' से होकर नहीं जाता। रास्ता उन 'साझा हाथों' से होकर जाता है जो झाड़ुआ के खेतों में एक-दूसरे को थामे हुए हैं। 'अड़जी-पड़जी' हमें याद दिलाती है कि खेती केवल एक व्यापार नहीं है, बल्कि एक सामुदायिक उत्सव और जीवन पद्धति है। यदि हम वास्तव में किसान और मजदूर दोनों को बचाना चाहते हैं, तो हमें अपनी आधुनिक नीतियों में झाड़ुआ के इस 'अड़जी-पड़जी' मॉडल को जगह देनी होगी। स्थानीय ज्ञान और परंपराओं का सम्मान ही वह एकमात्र पुल है, जो वर्तमान के संकट और भविष्य की खुशहाली को जोड़ सकता है। यह समय है, मशीनों के शोर को कम करने और सहयोग की उन दबी हुई आवाजों को सुनने का है।







हिंद महासागर में बढ़ेगी भारत की ताकत !

आप अरब में हमारे मेन पार्टनर हैं- पुतिन

**हिंद महासागर**  
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कोमोरोस के विदेश मंत्री म्बाए मोहम्मद से मुलाकात की। एक्स पर एक पोस्ट में जयशंकर ने लिखा कि आज कोमोरोस के विदेश मंत्री म्बाए मोहम्मद से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमने स्वास्थ्य, खेल, अवसंरचना और क्षमता निर्माण में सहयोग पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच नियमित मुलाकातों के महत्व पर सहमति बनी। एक दिन पहले ही मोहम्मद शनिवार को होने वाली दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री की राजधानी की यात्रा से भारत और कोमोरोस संघ के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। अपने आधिकारिक संदेश में उन्होंने कहा कि दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे कोमोरोस के विदेश मंत्री @टुै75 का हार्दिक स्वागत है। उनकी यात्रा से भारत और कोमोरोस संघ के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। विदेश मंत्रालय के संक्षिप्त विवरण के अनुसार, भारत ने जून 1976 में कोमोरोस के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और अंतानानारिवो स्थित भारतीय



दूतावास को कोमोरोस के लिए भी मान्यता प्राप्त है। भारत और कोमोरोस के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों देश कई क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर समान विचार रखते हैं। कोमोरोस 2012 से हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और 2017 से अंतर्राष्ट्रीय सीर गठबंधन का सदस्य है। कोमोरोस में भारतीय प्रवासी समुदाय में लगभग 250 व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश व्यापार, व्यवसाय

और अन्य पेशों में लगे हुए हैं। कोमोरोस के आर्थिक विकास में उनकी भूमिका सर्वोच्च है। भारत दूसरे भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक (आईएफएमएम) की मेजबानी करेगा। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात करेंगे। विदेश मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अरब लीग के अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्री और अरब लीग के महासचिव दूसरे भारत-अरब

विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विदेश मंत्रियों की यह बैठक 10 साल के अंतराल के बाद हो रही है। पहली बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी। पहली एफएमएम में, मंत्रियों ने सहयोग के पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की: अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति, और इन क्षेत्रों में गतिविधियों का एक समूह प्रस्तावित किया।



हुए कहा कि नवंबर में यूई में रूसी संस्कृति दिवस सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे। उन्होंने दीर्घकालिक सहयोग प्रयासों के तहत अमीरात में एक रूसी विश्वविद्यालय और एक युवा विज्ञान पार्क स्थापित करने की योजनाओं का भी जिक्र किया। पर्यटन क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, संयुक्त अरब अमीरात आने वाले रूसी पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अकेले 2025 के पहले नौ महीनों में ही लगभग 15 लाख रूसियों ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि है। राष्ट्रपति अल नाहयान ने विश्वास

व्यक्त किया कि 2026 रूस के लिए प्रगति और विकास का वर्ष होगा और द्विपक्षीय संबंधों में और अधिक समृद्धि आएगी। उन्होंने मॉस्को के साथ सहयोग को गहरा करने और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले वर्ष हस्ताक्षरित सेवा व्यापार और निवेश संबंधी समझौते, साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और यूरोशियन आर्थिक संघ (ईएईयू) के बीच आर्थिक साझेदारी समझौता, व्यापार विस्तार, पारस्परिक निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

## चीन को ताईवान का एक और झटका !

**ताइवान**  
शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कैपस के इंटरनेट नेटवर्क डिजिटल मामलों के मंत्रालय द्वारा सुरक्षा खतरों के रूप में वर्गीकृत छह चीनी एप्लिकेशनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करेंगे। ताइवान के डिजिटल मंत्रालय ने पिछले महीने घोषणा की थी कि ये ऐप सूचना सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं और लोगों से अपनी डिजिटल सुरक्षा का ध्यान रखने का आग्रह किया था। इस चेतावनी का जिक्र करते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि टिकटोंक पर हानिकारक सामग्री होस्ट करने के लिए कई देशों द्वारा जुमाना भी लगाया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह आधिकारिक उपकरणों पर इन छह एप्लिकेशनों को

डाउनलोड करने, इंस्टॉल करने और उपयोग करने पर रोक लगाएगा और स्कूलों और मंत्रालय एजेंसियों में ब्लॉक और ब्लॉक हॉटस्पॉट सहित कैपस नेटवर्क पर भी इन तक पहुंच को ब्लॉक करेगा। TANet शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों और शिक्षकों को प्रदान की जाने वाली एक निःशुल्क नेटवर्क सेवा है। ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान में देश भर में 9,000 से अधिक हॉटस्पॉट हैं, जिनका संचालन डिजिटल मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शिक्षा उप मंत्री चू चुन-चांग ने कहा कि यह कदम साइबर सुरक्षा प्रबंधन अधिनियम और बाल एवं किशोर कल्याण एवं अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत कैपस नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के प्रयासों का हिस्सा है।

उन्होंने आगे कहा कि मंत्रालय 2014 से ही कैपस नेटवर्क को अनुचित सामग्री से नियमित रूप से सुरक्षित कर रहा है। ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने कहा कि स्कूलों को शिक्षण गतिविधियों में उच्च जोखिम वाले अनुप्रयोगों का उपयोग करने से बचना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शैक्षिक सामग्री उपयुक्त हो। मंत्रालय ने कक्षा में उपयोग के लिए अपनी मीडिया और साहित्यिक शिक्षा वेबसाइट पर उपलब्ध दो डेटाबेस की ओर भी इशारा किया, जिनमें से एक शियाओहोंग्सु पर और दूसरा लघु-रूप सामग्री पर केंद्रित है। चू ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी करना और उन्हें ऑनलाइन जीवन और



वास्तविक दुनिया के बीच स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में मार्गदर्शन देना महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रालय युवाओं के लिए बेहतर शिक्षण और विकास का

माहौल बनाने के लिए स्कूलों और अभिभावकों के साथ सहयोग जारी रखेगा, जैसा कि ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है।

## इमरान खान का पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में आंखों से संबंधित चिकित्सा परीक्षण हुआ



**पाकिस्तान**  
पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारन ने पुष्टि की है कि जेल में बंद पीटीआई के संस्थापक इमरान खान का पिछले सप्ताह इस्लामाबाद के एक अस्पताल में आंखों से संबंधित चिकित्सा परीक्षण हुआ था। जियो न्यूज से बात करते हुए तारन ने बताया कि रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री को 24 जनवरी की रात को "20 मिनट" की चिकित्सा प्रक्रिया के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएम) ले जाया गया था। तारन ने कहा कि आंखों के

विशेषज्ञों ने अडियाला जेल में उनकी जांच की, जिसके बाद उन्होंने एक छोटी सी चिकित्सा प्रक्रिया के लिए उन्हें पीआईएम ले जाने की सलाह दी। पिछले शनिवार की रात, इन नेत्र चिकित्सकों और विशेषज्ञों की सलाह पर उन्हें पीआईएम ले जाया गया। उन्होंने आगे बताया कि पीआईएम में इमरान की आंखों की आगे जांच की गई और उनकी लिखित सहमति के बाद, 20 मिनट की चिकित्सा प्रक्रिया की गई, जिसके बाद उन्हें महत्वपूर्ण निदेशों के साथ वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। आगे जानकारी देते हुए तारन ने कहा, "चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान उनके सभी स्वास्थ्य संकेत स्थिर थे।

**ईरान**  
ईरान ने आईआरजीसी को आतंकवादी समूह घोषित किए जाने के बाद यूरोपीय संघ पर करारा जवाब दिया। करारा जवाब देते हुए ईरान ने कहा है कि वह उन यूरोपीय संघ के देशों की सेनाओं को आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल करेगा, जिन्होंने आईआरजीसी को आतंकवादी समूह घोषित किया है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यूरोपीय संघ निश्चित रूप से जानता है कि इस्लामी सलाहकार सभा के प्रस्ताव के अनुसार, उन देशों की सेनाओं को आतंकवादी संगठन माना जाता है जिन्होंने इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कोर के खिलाफ यूरोपीय संघ के हालिया प्रस्ताव में भाग लिया है। इसलिए, इसके परिणाम उन

यूरोपीय देशों को भुगतने होंगे जिन्होंने ऐसा कदम उठाया है। ईरान ने कहा है कि इस्लामिक रिवालयूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बाद यूरोप को मूर्खतापूर्ण कृत्य के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दिल्ली दौरे पर आए फिलिस्तीनी विदेश मंत्री वर्सन अघाबेकियन शाहिन ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता सभी के लिए चिंता का विषय है। फिलिस्तीनी मंत्री अमेरिका-ईरान के बीच जारी तनाव और गाजा शांति के विषय पर बोल रहे थे। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को अमेरिकी नौसेना का एक विध्वंसक पोत इजरायल के इलात बंदरगाह पर पहुंचा। रिपोर्ट में सैन्य सूत्रों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी गई है। यह घटनाक्रम

उनके घनिष्ठ चर्चा को पिछले शुक्रवार को अदालत में सुनवाई के लिए जाते समय हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम (PECA) के तहत मामला दर्ज कर दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि दंपति ने एक्स पर ऐसी सामग्री साझा की थी जो कथित तौर पर जातीय विभाजन को बढ़ावा देती थी।



वाशिंगटन और ईरान के बीच तनाव के बीच हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मित्र और जॉर्डन के साथ इजरायल की सीमाओं के पास, अकाबा की खाड़ी पर स्थित दक्षिणी बंदरगाह पर विध्वंसक पोत का आगमन पूर्व नियोजित था और अमेरिकी और इजरायली सेनाओं के बीच चल रहे सहयोग का हिस्सा है। तुर्की के राष्ट्रपति तैय्यप एर्दोगन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से कहा कि तुर्की ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव कम करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस बात पर जोर दिया कि तुर्की ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव कम करने और मुद्दों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है।

अखंड भारत संदेश

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक

स्वामी श्री योगी सत्यम् फॉर

योग सत्संग समिति

द्वारा विपिन इण्टरप्राइजेज

1/6C माधव कुंज

कटरा, प्रयागराज से मुद्रित

एवं

क्रियायोग आश्रम एण्ड अनुसंधान संस्थान

झुंसी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश

से प्रकाशित

सम्पादक

स्वामी श्री योगी सत्यम्

RNI NO. UPHIN/2001/09025

प्रबन्धक

अनूप मिश्रा

ऑफिस मो.:

9565333000

Email:

akhandbharratsandesh1@gmail.com

सभी विवादो का न्याय क्षेत्र

प्रयागराज होगा

## सऊदी अरब-UAE से ईरान, यमन कैसे बना जंग का मैदान ?

**सऊदी अरब**  
साल 2008 में 19 साल की एक लड़की केरला से लगभग 3000 किमी दूर एक दूसरे मुल्क पहुंचती है कुछ दिनों बाद वह भारत में अपनी मां के पास फोन करती है कहती है मां मुझे नौकरी मिल गई है अब हमारे घुरे दिन खत्म होने वाले हैं दरअसल कुछ ही दिनों में उस लड़की को एक सरकारी अस्पताल में काम मिल गया था फिर वहां रहते-रहते लड़की में आत्मविश्वास बढ़ा 2014 में उसने खुद का क्लिनिक खोलने की तरफ पहला कदम बढ़ा या घड़ी के साथ समय का कांटा बदला लगभग एक दशक बाद आज वो लड़की मिडिल ईस्ट के देश की जेल में बंद पाई गई और वहां के राष्ट्रपति ने उसे मौत की सजा सुना दी। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जानी

थी। उससे ठीक तीन दिन पहले मामला देश की सर्वोच्च अदालत के पास भी पहुंचा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी को रोकने के लिए वह कुछ खास नहीं कर सकती। ये देश दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से जैसा नहीं है। वो दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है। यहां हूती का दबदबा चलता है। ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि पूरी कहानी में इसका जिक्र बारम्बार होने वाला है। एक तरफ फांसी की तैयारी चल रही थी तो दूसरी तरफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में इसे रुकवाने के प्रयास लगभग छिन होते जा रहे थे। 16 जुलाई को निमिषा को फांसी होनी थी लेकिन आखिर समय पर ये टल गई। जिसके बाद कहा जाने लगा कि जो

हूती नियंत्रित शासन अमेरिका तक की नहीं सुनता वहां एक मौलाना ने इसे रुकवा दिया। केरल की नर्स निमिषा प्रिया की सजा-ए-मौत टाल दिए जाने के पीछे केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबु बकर

अहमद की भूमिका को भी खूब चर्चा हुई। आज के ग्लोबमास्टर में आपको मिडिल ईस्ट के एक और देश लिए चलते हैं। जिसके उत्तर में सऊदी अरब है और पूर्व में ओमान की सीमा है। बाकी

दिशाओं में फैला है विशाल समुद्र। ये देश यमन है। यमन का इतिहास इसकी शुरूआत 628 ईस्वी से करते हैं, जब यहां इस्लाम आया। इससे पहले तक इस क्षेत्र में यहूदी और ईसाइयों का गहरा प्रभाव था। हालांति 628 ईस्वी में पैगम्बर मोहम्मद साहब के समय यहां इस्लाम से पहुंचा और यह क्षेत्र बिना किसी बड़े युद्ध के इस्लामी शासन का हिस्सा बन गया। इसके बाद यहां अलग-अलग खिलाफत और इमामत का शासन रहा। उस्मानी साम्राज्य ने भी यहां पर दो बार हुकुमत की है। एक समय में यमन को 'अरबिया फेलिक्स' भी कहा जाता है था, जिसका मतलब खुशहाल होता है। 1990 से पहले यमन दो हिस्सों में बंटा हुआ था। इससे पहले यह देश उत्तर यमन और

दक्षिण यमन में बंटा हुआ था। हालांकि 22 मई 1990 को यह देश एक बार फिर से एकजुट हो गया। इसके बाद यहां हतियों की एंट्री होती है। शिया मुस्लिम गुट जो अमेरिका से भी नहीं डरता कोई बगावत करता है और समूह में करता है तो विद्रोही गुट के नाम से पहुंचा और यह क्षेत्र किसी बड़े युद्ध के इस्लामी शासन का हिस्सा बन गया। इसके बाद यहां अलग-अलग खिलाफत और इमामत का शासन रहा। उस्मानी साम्राज्य ने भी यहां पर दो बार हुकुमत की है। एक समय में यमन को 'अरबिया फेलिक्स' भी कहा जाता है था, जिसका मतलब खुशहाल होता है। 1990 से पहले यमन दो हिस्सों में बंटा हुआ था। इससे पहले यह देश उत्तर यमन और